

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]	नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2013/चैत्र 19, 1935
No. 67]	NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2013/CHAITRA 19, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2013

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डायक्लोफैनेक सोडियम के आयातों पर अधिरोपित निर्णायक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

सं. 15/3/2013-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है (ने चीन जन. गण. (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डायक्लोफैनेक सोडियम (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर अपनी दिनांक 29 मई, 2008 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की केंद्रीय सरकार से सिफारिश की थी और, उक्त अंतिम जांच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग ने दिनांक 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या 91/2008 के तहत संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया था।

समीक्षा के लिए अनुरोध

- 2. यतः, सीमा शुल्क प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1995 में दी गई शर्तों के अनुरूप अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण न कर दिया गया हो तो अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा।
- 3. और, उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी प्राधिकारी से यह अपेक्षित होता है कि वह ऐसे साधन की समाप्ति की तारीख से पहले युक्तिसंगत समयावधि के अंतर्गत घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध पर समीक्षा करेंगे कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।
- 4. और यतः, घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मैसर्स आरती इग्स लिमिटेड और मैसर्स आमोली आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें एतद्पश्चात आवेदक कहा गया है) ने, उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत, विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र देकर प्राधिकारी से ऐसी समीक्षा करने का अनुरोध किया है तथा प्राधिकारी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों के आधार पर विचार करते हैं कि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच प्रक्रिया को प्रारंभ करना यह आकलन करने के लिए उपयुक्त होगा कि क्या उक्त शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता पाटन को दूर करने के लिए आवश्यक है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाए या उसमें कोई अंतर कर दिया जाए अथवा दोनों रूपों से क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति बने रहने की संभावना है।

समीक्षा के आधार

- 5. यह अनुरोध प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए है। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है और चूंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप एवं उसकी प्रमात्रा अपर्याप्त है इसलिए संबद्ध देश से पाटन के कारण घरेलू उद्योग की निरंतर क्षिति हो रही है। आवेदनकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि संबद्ध देश के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षिति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- 6. आवेदक यह भी दावा करते हैं कि पाटनरोधी उपाय का प्रतिसंहरण करने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति बढ़ जाएगी और इस कारण इस शुल्क को पांच वर्षों की अन्य अविध के लिए बनाए रखना अपेक्षित है।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड और मैसर्स अमोली आर्गनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है अर्थात वे 72 प्रतिशत तक का उत्पादन करते हैं और इसलिए वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं।

जांच शुरूआत

8. समीक्षा की आवश्यकता के पर्याप्त प्रमाण सिहत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समापन से पाटन एवं क्षिति की अवस्थिति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्द्वारा एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

9. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में 29 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/4/2007- डीजीएडी के तहत विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया है :- "विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण के मूल का अथवा वहां से निर्यातित डायक्लोफैनेक सोडियम है। डीएफएस एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। डीएफएस एक गैर-स्टीराइडल एण्टी इन्फ्लेमेटरी ड्रग (एन एस ए आई डी) है जो अर्थराइटिस और गहरी चोट जैसी स्थितियों में होने वाले दर्द और जलन को कम करने के लिए लिया जाता है। इस उत्पाद को भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा शुल्क प्रशुल्क शीर्षक संख्या 2942.0090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क एवं आई टी सी वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जांच के दायरे के अंतर्गत किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है"।

10. चूंकि वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है। इस अवधि के दौरान उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं आया है।

प्रक्रिया

- 11. प्रस्तुत जांच यह निर्धारित करेगी कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षिति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी। प्राधिकारी यह जांच करेंगे कि क्या शुल्क का सतत अधिरोपण पाटन को दूर करने के लिए आवश्यक है और यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाए या उसमें कोई अंतर कर दिया जाए अथवा दोनों रूपों से क्षिति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।
 - (i) यह समीक्षा दिनांक 29 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/4/2007-डीजीएडी के सभी पहलुओं को कवर करेगी।
 - (ii) इस समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन गण है।
 - (iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अविध (पीओआई) अक्तूबर, 2011 दिसम्बर, 2012 है तथापि, क्षति जांच अविध में अप्रैल 2009 मार्च 2010, अप्रैल 2010 मार्च 2011, अप्रैल 2011 मार्च 2012 तथा जांच की अविध शामिल होगी।
 - (iv) इस समीक्षा पर नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 तथा उनके अधीन बने नियमों के सभी प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के जिरए, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग कमरा सं. 240, उद्योग भवन,

नई दिल्ली-110011

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयाविध के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अ-गोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनिधक समय के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समयाविध के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावितयों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्त्त करना

- 16. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग-अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए : (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि (और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि । उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' अथवा ''अगोपनीय'' लिखा जाना चाहिए।
- 17. गोपनीय चिन्ह के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमित प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 18. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेत् मुहैया कराना चाहिए।
- 19. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।
- 20. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2013

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of definitive anti-dumping duty imposed on imports of Diclofenac Sodium originating in or exported from the China PR.

No. 15/3/2013-DGAD:—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had recommended to the Central Government imposition of the anti-dumping duty on the imports of Diclofenac Sodium (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) vide its Final Findings Notification dated 29th May, 2008. And, on the basis of the said Final Findings, the Department of Revenue, vide Notification Nos. 91/2008-Customs dated 30th July, 2008, had levied the definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Request for Review

- 2. WHEREAS, in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.
- 3. AND, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- 4. AND, WHEREAS, in terms of the above provisions, M/s. Aarti Drugs Ltd. and M/s. Amoli Organics Pvt. Ltd (hereinafter referred to as the applicants) representing the Domestic Industry have approached the Authority with a duly substantiated application requesting for such a review, and the Authority on the basis of prima facie evidence considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied or both.

Grounds for review

- 5. The request is for continuation of the anti-dumping duties in force. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of anti-dumping duty on import of the subject goods from the subject country and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country as the form and quantum of anti-dumping duty in force has been insufficient. The applicants have further argued that expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 6. The applicants also claim that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.

Domestic industry

7. The application has been filed by M/s. Aarti Drugs Ltd. and M/s. Amoli Organics Pvt. Ltd. on behalf of the domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods to the tune of 72% and, therefore, constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

Initiation

8. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a Sunset Review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Product under Consideration

9. In the original investigation, vide notification No. 14/4/2007-DGAD dated 29th May, 2008, the Designated Authority had defined product under consideration as under:

"The product under consideration is Diclofenac Sodium, originating in or exported from China PR. DFS is a basic organic chemical, normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. DFS is a non-steriodal anti-inflammatory drug (NSAID) taken to reduce inflammation and an analgesic reducing pain in conditions such as in arthritis or acute injury. This product is classified under Customs Tariff heading no. 2942.0090 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

10. Present investigation being a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product over the period.

Procedure

- 11. The investigation will determine as to whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.
 - i). The review will cover all aspects of Notification No. 14/4/2007-DGAD dated 29th May, 2008.
 - ii). The country involved in this review investigation is China PR.

- iii). The period of investigation (POI) for the purpose of the present review is from October 2011—December 2012. The injury investigation period will, however, cover the periods Apr '09-Mar '10, Apr '10-Mar '11, Apr '11-Mar '12 and the POI.
- iv). The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

12. The exporters in the subject country, their governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority

Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties

Ministry of Commerce and Industry

Department of Commerce

Room No 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

- 14. Any information relating to the present review should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.
- 15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within 40 days from the date of publication of this Notification.

Submission of information on confidential basis

- 16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets- (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
- 17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Five (5) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
- 18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may

indicate that such information is not susceptible to summary and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

- 19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
- 20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

21. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority